

from India during the year 1961-62 is Rs. 3,91,26,287/-.

(b) The target of export of fish products is Rs. 12 crores by the end of the Third Five Year Plan.

(c) and (d). There is still a considerable scope for exploiting the marine resources of the Arabian Sea. A number of schemes under the Third Plan such as Mechanisation of fishing craft, supply of new types of gear, pilot fishing, exploratory deep-sea fishing, oceanographic and biological research, etc. are directed towards increasing the catches of sea fish. Large scale exploitation of our marine fish resources by collaboration with foreign countries is also under consideration.

Agriculture Production

779. { Shri A. K. Gopalan:
Shri Umanath:
Shri P. Kunhan:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether any agency of the agricultural Department of the Government of the United States of America had undertaken any survey of prospects of agricultural production in India by 1975-76;

(b) if so, what is the agency and who bore the expenditure of the survey; and

(c) the main findings of the survey and the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). The National Council of Applied Economic Research, New Delhi, undertook a study of the long term supply of and demand for selected agricultural commodities over the period 1960-61 to 1975-76; this study was sponsored by the Foreign Agricultural Service, Department of Agriculture of the U.S. Government. The findings of this survey have been published in March, 1962 in the form of a period report,

entitled "Long term projections of demand for and supply of selected agricultural commodities 1960-61 to 1975-76".

Fishing Trawlers

780. { Shri A. K. Gopalan:
Shri Umanath:
Shri P. Kunhan:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government propose to involve a project for manufacture of Big Fishing Trawlers;

(b) if so, what is the target proposed for the Third Five Year Plan;

(c) how Government propose to distribute them; and

(d) how many trawlers Government propose to allot to Kerala and by what time?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) No such proposal is under consideration.

(b) to (d). Does not arise.

दिल्ली के पास पास होटल व मोटल का निर्माण

७८१. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भगवत सा आजाद :
श्री दि० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्र २२ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली व नई दिल्ली के चारों ओर होटल व मोटल बनाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौबहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : दिल्ली में होटल बनाने के प्रस्ताव कई पार्टियों से प्राप्त हुए हैं, परन्तु मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो क्षेत्र

'व्यापारिक' क्षेत्र घोषित किये गये हैं उन में उचित जगह उपलब्ध न होने तथा रिहायशी क्षेत्रों में होटलों के निर्माण पर प्रतिबन्ध होने के कारण इन प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी पर्यटन विभाग की सिफारिशों के फलस्वरूप दिल्ली विकास अधिकारी तथा नगर योजना संगठन ने रिहायशी क्षेत्रों में होटल बनाने की अनुमति दे दी है, बशर्ते कि होटलों के साइज, डिजाइन और तेल क्षेत्र के अनुपात सम्बन्धी कुछ शर्तें पूरी कर दी जायें। इन विभिन्न अनुबन्धों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और दिल्ली विकास अधिकारी से एक औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच दिल्ली और उसके चारों ओर होटल बनाने के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग से बाधाओं को दूर करने वाली पार्टियों का सम्पर्क नगर योजना संगठन से स्थापित कर दिया गया है क्योंकि ऐसे प्रस्तावों की प्रारम्भिक जांच से इस संगठन का सम्बन्ध है।

रिहायशी क्षेत्रों में होटल निर्माण की नयी सुविधा के अलावा होटल उद्योग को राज्य वित्त निगम से ऋण लेने की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा होटल उद्योग को औद्योगिक वित्त निगम से ऋण लेने की सुविधा १९५८ से प्राप्त है। होटल उद्योग को सबसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन यह दिया गया है कि यदि नये होटल कुछ शर्तों को पूरा करें तो अप्रैल, १९६१ से उन्हें प्रथम पांच वर्षों तक आय-कर से छूट दे दी जायेगी। पर्यटन विभाग और सहायता भी देता है जिसमें जरूरी साज-सामान और रसद के आयात के लिये सिफारिशें भी शामिल हैं।

उष्णदेशीय अंतरिक्ष विज्ञान की राष्ट्रीय संस्था

७८२. श्री भक्त वर्मान : क्या परिष्कृत तथा संशोधन मंत्री १४ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उष्णदेशीय अंतरिक्ष विज्ञान की राष्ट्रीय संस्था को स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

परिष्कृत तथा संशोधन मंत्रालय के उपमंत्री (श्री मोहम्मद अली) : इंस्टीट्यूट को कायम करने के लिये खास किस्म के साज-सामान, माहिरों और फेलोशिप को हासिल करने में मदद के लिये यूनाइटेड नेशन्स स्पेशल फंड के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है। इंस्टीट्यूट को शुरू-शुरू में चलाने के लिए कुछ स्टाफ भी मंजूर किया गया है।

Agricultural Education and Research

783. { Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) how long Government will take to consider the report of the Second Joint Indo-American team on Agricultural Education and Research;

(b) whether any recommendations have been accepted by Government; and

(c) what steps Government are taking to implement the recommendations and what are the financial implications thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c): The report is under active consideration of the Government. Steps are being taken to expedite decisions on the recommendations.

Food Production in Andhra Pradesh

784. Shri P. Venkatasubbalah: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government have promised to the Government of Andhra Pradesh to give additional financial assistance to the tune of about 7 crores of rupees during the Third Five Year Plan if there is additional production of about hundred thousand tons of foodgrains over and above the target of food production; and